The present estimated cost of the Sindri Modernisation project is Rs. 152.04 crores. The project which was originally expected to be mechanically completed by November 1977 is now expected to be completed in May 1978. The Modernisation scheme will not only maintain the supply of ammonia for the manufacture of ammonium sulphate in the existing facilities but will result in an additional fertilizer capacity of 129,000 tonnes per annum of nitrogen in the form of urea

मेरठ में उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने का प्रस्ताव

7286. **श्री कैलाश प्रकाश** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने मेरठ में उच्च न्यायालय की बेंच खोलने की सिफारिश की है, और यदि हां, तो यह सिफारिश कब प्राप्त हुई, और

(ख) क्या बार एसोसिएशन, मेरठ से भी उन्हें कोई संकल्प प्राप्त हुआ है जिसमें मेरठ में उच्च न्यायालय की बेंच खोलने की मांग की गई है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) मार्च, 1978 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि उनकी राय है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए उच्च न्यायालय की एक बैंच की स्थापना का औचित्य है। उन्होंने ऐसे किसी स्थान विशेष की सिफारिश नहीं की है जहां ऐसी बैंच स्थापित की जाए। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि इस विषय में ऐसे कुछ पहलुओं पर जैसे प्रस्तावित बैंच की अधिकारिता के भीतर रखे जाने वाले जिलों, बैंच स्थापित करने के स्थान आदि पर, राज्य सरकार विचार कर रही है।

(ख) जी हां। राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह इस विषय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के विचार जान कर सूचित करे।

Issue of Licences to Foreign Drug Firms

7287. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2832 dated 14th March, 1978 regarding nationalisation of foreign drug firms and state:

(a) whether many foreign drug firms have been given licences and letters of intent to produce various types of drugs since the submission of the Hathi Committee Report;

(b) if so, names of the firms who have been given licences/letters of intent to-date since the submission of the Hathi Committee Report;

(c) types of licences given to each firm, and

(d) the reasons why so much time is being taken to finalise Government's decisions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) to (c). Thirteen foreign drug manufacturing companies (having direct foreign equity exceeding 40 per cent) have been granted 23 Industrial Licences/COB Licences/Letters of Intent for the manufacture of drugs and pharmaceuticals since the submission of the Hathi Committee Report to date.

A statement furnishing the requisite information is attached.

(d) A statement containing Government's decisions on the Report of the (Hathi) Committee on Drugs and Pharmaceuticals has been laid on the Table of the House on the 29th March, 1978.